एल. एल. सुधाकर रेड्डी और अन्य

बनाम

एपी और ओआरएस का राज्य।

9 अगस्त, 2001

[सैयद शाह मोहम्मद कादरी और एस. एन. फुकान, जे. जे.]

आंध्र प्रदेश भूमि हड़पना (निषेध) अधिनियम, 1982: धारा 8 और 17-ए-कथित रूप से हड़पी गई भूमि-विशेष न्यायालय के समक्ष मंडल राजस्व अधिकारी द्वारा आवेदन-अनुमत-लिखित याचिका-सी उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित करते हुए खारिज कर दिया गया कि रिट याचिकाकर्ताओं के पास धारा 17-ए के तहत समीक्षा का अवसर था-इसके अलावा, वे स्वामित्व और अधिकार की घोषणा के लिए मुकदमा दायर कर सकते थे-गुणागुण के आधार पर उच्च न्यायालय ने विशेष न्यायालय के आदेश को उचित ठहराया-आयोजित, उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी की कि रिट याचिकाकर्ताओं को धारा 17 ए के तहत समीक्षा के उपचार का लाभ उठाया जा सकता था, गुणागुण पर कोई राय व्यक्त नहीं करनी चाहिए थी-डी मुकदमे के उपचार के संबंध में, धारा 17 ए के तहत।8 (2), आर/ws.15, भूमि के संबंध में रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा स्वामित्व की घोषणा के लिए कथित रूप से हड़पा गया मुकदमा बनाए रखने योग्य नहीं होगा-उच्च न्यायालय के आदेश को दरकिनार कर दिया गया-उच्च न्यायालय रिट याचिका पर नए सिरे से फैसला करेगा।

धारा 8 (2) आर/w.s.15-कथित रूप से हड़पी गई भूमि-के संबंध में स्वामित्व का मुकदमा रखरखाव योग्य नहीं रखा गया।

भारत का संविधान, 1950; अनुच्छेद 226-ए. पी. के तहत विशेष न्यायालय के आदेश के खिलाफ याचिका लिखें। भूमि हड़पना (निषेध) अधिनियम, 1982-उच्च

न्यायालय ने यह देखते हुए कि धारा 17-ए के तहत समीक्षा का उपाय उपलब्ध था और योग्यता के आधार पर रिट याचिका को भी खारिज कर दिया।

विशेष न्यायालय के आदेश को उचित ठहराते हुए-उच्च न्यायालय को गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं करनी चाहिए थी-आंध्र प्रदेश भूमि हड़पना (निषेध) अधिनियम, 1982 में।

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 6731/1994

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के 1992 की रिट अपील संख्या 680 में 23.7.1992 दिनांकित निर्णय और आदेश से

के साथ

याचिका सं. 904/1992 लिखें।

ए. श्री पी. एस. मिश्रा, श्री ए. मारियारपुथम, सुश्री अरुणा माथुर, सुश्री एस. रानी, श्री अनुर्ग डी. माथुर, मेसर्स अर्पुथम के लिए, अरुणा एंड कंपनी Appellants.Ms के लिए। उत्तरदाताओं की ओर से के. अमरेश्वरी, श्री जी. प्रभाकर और श्री के. राम कुमार।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश दिया गया थाः यह अपील 23 जुलाई, 1992 को लिखित अपील संख्या 680/1992 में हैदराबाद में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की खंड पीठ के फैसले और आदेश के खिलाफ निर्देशित की गई है, जिसमें विद्वान एकल के आदेश की पुष्टि की गई है।

न्यायाधीश ने 16 जून, 1992 को डब्ल्यू. पी. सं. <आई. डी. 1 में पारित किया जिसके द्वारा अपीलार्थियों द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया गया था।

मंडल राजस्व अधिकारी, गोलकोंडा, राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए पहले प्रतिवादी आंध्र प्रदेश ने आंध्र प्रदेश भूमि हड़पना (निषेध) अधिनियम, 1982 (इसके बाद) की धारा 8 के तहत एक आवेदन दायर किया।

अधिनियम (संक्षेप में विशेष न्यायालय) के तहत विशेष न्यायालय में 1988 के एल. जी. सी. 21 के रूप में संदर्भित)। भौतिक आरोप यह है कि आवेदन यह था कि पहले अपीलकर्ता ने सर्वेक्षण संख्या 403/1 में 5 एकड़ की सीमा तक सरकारी भूमि का अतिक्रमण किया, जो शेखपेट गाँव, बंजारा रोड, संख्या 10, हैदराबाद (संक्षेप में 'विवादित भूमि') में स्थित है, भूखंड ई बनाया और उन्हें विशेष न्यायालय के समक्ष 2 से 15 उत्तरदाताओं को बेच दिया, जो थे इच्छुक के रूप में माना गया persons.It आरोप लगाया गया था कि सरकार के अनुसार शेखपेट गाँव के सर्वेक्षण सं. 403/1 में अभिलेख भूखंड nos.11,12 औ र 13 गैर-मान्यता प्राप्त भूखंड थे और उन्हें सरकारी lands.On के रूप में माना जाता था कि विशेष न्यायालय ने मामले का संज्ञान लिया और अधिनियम की धारा 8 (6) के तहत अधिसूचना जारी की। 7 नवंबर, 1988। सत्यापन रिपोर्ट के अनुसार राजस्व अधिकारी द्वारा रखी गई सामग्री पर, विवादित भूमि के कब्जे वाले व्यक्तियों को भी जारी किया गया था, वे विशेष न्यायालय में एल. जी. सी. के पक्षकार थे, उन्हें इस में शामिल नहीं किया गया है, पहले अपीलार्थी ने अनुरोध किया कि वह विवादित भूमि को इसके जी मालिकों और मालिकों, अपीलकर्ताओं 2 से 4 से खरीदने के लिए सहमत हो गया था, और समझौते के तहत कब्जा प्राप्त किया था, इस आरोप से इनकार किया कि उसने विवादित भूमि पर कब्जा कर लिया था।

अभिलेख पर रखे गए साक्ष्य पर विचार करने के बाद विशेष न्यायालय ने कहा कि सरकार विवादित भूमि की मालिक है और एच प्रतिवादी भूमि हड़पने वाले हैं और उन्हें ए. पी. के एल. एल. सुधाकर रेड्डी v.STATE से बेदखल करने का आदेश दिया।

n विवादित land.It को स्पष्ट किया गया था कि धारा 8 की उप-धारा 7 ए के प्रावधान के तहत नोटिस issued.Thus नहीं था, प्रथम प्रतिवादी (LGC 21/88) द्वारा दायर आवेदन को विशेष न्यायालय द्वारा 1 जून, 1989 को अनुमति दी गई थी।

2 से 4 तक के अपीलार्थी जो विशेष न्यायालय के समक्ष पक्षकार नहीं थे, वे डब्ल्यू. पी. सं. <आई. डी. 1 में उच्च न्यायालय के समक्ष विशेष न्यायालय के उक्त आदेश की वैधता को चुनौती देने में अपीलार्थी सं. 1 में शामिल हो गए।

मामले को देखने वाले न्यायाधीश ने यह विचार व्यक्त किया किः(1) अपीलार्थियों के पास अधिनियम की धारा 17-ए के तहत विवादित आदेश की समीक्षा करने का अवसर था; (2) यदि वे विशेष न्यायालय के फैसले से व्यथित महसूस करते हैं तो उन्हें अपने अधिकार की घोषणा के लिए मुकदमा दायर करने से कुछ भी नहीं रोकता है और अधिकार; और (3) मामले के गुण-दोष पर विशेष न्यायालय का निर्णय था उसके समक्ष रखे गए साक्ष्य के आधार पर पूरी तरह से न्यायोचित, विशेष न्यायालय में अधिकार क्षेत्र की कोई कमी नहीं थी, रिकॉर्ड के सामने कोई त्रुटि स्पष्ट नहीं थी और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का कोई उल्लंघन नहीं था।

विद्वान एकल न्यायाधीश के उक्त आदेश पर उच्च न्यायालय की खंड पीठ के समक्ष रिट अपील संख्या 680/92 में सवाल उठाया गया था।

ऊपर उल्लिखित निष्कर्षों को दोहराया और 23 जुलाई, 1992 को रिट अपील को खारिज कर दिया।यह उस आदेश के खिलाफ है कि वर्तमान अपील विशेष अनुमति द्वारा दायर की गई है।

हमने श्री पी. एस. मिश्रा, विद्वान वरिष्ठ वकील को सुना है

अपीलार्थी और सुश्री के. अमरेश्वरी, ई उत्तरदाताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील हैं।

जिस दृष्टिकोण से हमने लिया है, हम इसके गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त करने का प्रस्ताव नहीं करते हैं कि यह अवलोकन करने के बाद कि अपीलकर्ता अधिनियम की धारा 17-ए के तहत समीक्षा पर उपचार का लाभ उठा सकते थे और अधिकार और अधिकार की घोषणा के लिए वाद, हमारे विचार में, विद्वान एकल न्यायाधीश को मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि उच्च न्यायालय द्वारा विशेष न्यायालय के निर्णय और आदेश पर अपनी मंजूरी की मुहर लगाने के बाद, समीक्षा आवेदन और मुकदमे का परिणाम मुकदमे के उपचार के संबंध में एक पूर्व-जी धारा (2) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, धारा 15 के साथ पढ़ा जाएगा।

इस तरह के विशेष न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में होता, एच 386 स्थानांतरित किया गया था विशेष न्यायालय को ए जैसे कि कार्रवाई के कारण जिन पर मुकदमे या कार्यवाही आधारित है, विशेष Court.In के गठन के बाद उत्पन्न हुए थे, अन्य शब्दों में अपीलकर्ताओं द्वारा स्वामित्व की घोषणा के लिए मुकदमा उपरोक्त कारण नहीं होंगे, एकल न्यायाधीश के आदेश की पुष्टि करने वाले चुनौती के तहत डिवीजन बेंच के आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है, रिट याचिका को उच्च न्यायालय की फाइल में बहाल कर दिया जाता है और मामला उच्च न्यायालय को भेज दिया जाता है। law.It के अनुसार रिट याचिका पर नए सिरे से निर्णय लेने के लिए अदालत को यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि हमने मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है और यह पक्षों के लिए ऐसी दलीलें उठाने के लिए खुला होगा जो law.The अपील में उनके लिए अनुमत हैं।

डब्ल्यू. पी. नं. 904/1992।

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ वकील श्री पी. एस. मिश्रा ने रिट याचिका को वापस लेने की अनुमति मांगी है और उचित relief.The रिट याचिका को वापस लिए जाने के कारण खारिज करने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता मांगी है।

पक्षकार अपील के साथ-साथ रिट याचिका में भी अपना खर्च स्वयं वहन करेंगे।

अपील स्वीकार कर ली गई और याचिका खारिज कर दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।